

19.10-22

पत्रावली पेश हुई।

बहस सुनी गई।

प्रार्थिनीगण की बहस है कि प्रार्थिनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मौजा भुका वगतसिंह पटवार हल्का भूका वगतसिंह के खेत खसरा नम्बर 635/1 रकबा 24.00 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थिनीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 4/12 हिस्सा संयुक्त कब्जा काश्त के आये हुये हैं तथा उक्त हिस्सों के अनुसार पक्षकार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इस पर पक्षकारान की ढाणीया, टांके, चारा तथा मवेशीयो के बाड़े इत्यादि बनें हुऐ हैं। प्रार्थिनीगण कादर खा की पुत्रीया होने से उपरोक्त भूमि मे अपना प्रत्येक 1/12-1/12 हिस्सा खातेदारी मे घोषित करवाने की अधिकारी है

  
सहायक कलेक्टर  
SDO सिंगधरी

अभी हाल ही में कादर खा ने अपनी पुत्रीयों के हक से वंचित करने की दुर्भावना से सम्पूर्ण आराजी की भूमि का भेंट पत्र विप्रार्थी सख्या 1 से 3 के पक्ष में कर दिया है जबकि कादर खा को अपना 1/12 हिस्सा से ज्यादा किया गया बेचान प्रारम्भ से ही शून्य है कादर को अपना सम्पूर्ण हिस्सा का बेचान प्रारम्भ ही शून्य है तथा उक्त बेचान के आधार पर विप्रार्थी सख्या 1 से 3 प्रार्थीगण को कब्जा से बेदखल करने पर आमदा है विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण का अपने घर-बार से बेघर होना पड़ेगा तथा उनके बच्चे व स्वयं भूख मरने की नौबत आ जावेगी प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात होगा तथा अपनी पुरखों की आराजी के हक से वंचित हो जावेगी प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। लिहाजा खेत मौजा भूका वगतसिंह के खेत खसरा नम्बर 635/1 रकबा 24.00 बीघा किस्म बरानी सोयम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी विप्रार्थीगण नहीं कर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे।

इसके विपरित विप्रार्थी सं. 1 से 3 कि बहस है कि विवादित आराजी ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खसरा संख्या 635/1 जो पैतृक खातेदारी का नहीं होकर कादरखान को आवंटन हुआ है जिससे उक्त खसरे पर कादरखान का हक है और अपने जीवन काल में सम्पूर्ण रकबे को बेचान करने की हैसियत रखता है। मुस्लिम विधि में पैतृक भूमि में भी लड़कियों को लड़कों के समान हिस्सा नहीं मिलता है जो मांग की गई है वह गलत है वैसे भी यह मांग इस खसरे पर लागू नहीं होती है। उक्त खसरा पैतृक नहीं होने से पुत्रिया उसमें अपना हिस्सा घोषित नहीं करवा सकती है। और कादरखान अपने जीवन काल में सम्पूर्ण रकबे को बेचान करने की हैसियत रखता है। प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। जिससे बेदखल करने का कथन मात्र काल्पनिक है। और प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है।

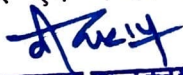
हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रवली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत आवेदन के जरिये विप्रार्थी सं. 3 से जो कि प्रार्थीगण का पिता है—से वारिसान की हैसियत से इस्तदुआ चाहते हुए प्रत्येक का 1/12-1/12 हिस्सा घोषित करवाते हुए मौके पर कब्जे काश्त के अनुरूप विभाजन चाहा गया है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान् मुस्लिम समुदाय से होने से मुस्लिम विधि अनुसार इस्तदुआ तलब की जानी थी। मुस्लिम विधि अनुसार सम्पत्ति का बंटवाड़ा करने की श्रेणी वारिसान में अलग-अलग रूप से निर्धारित हक हिस्से अनुसार की जानी है तथा हिन्दु रीति से पुत्र-पुत्रियों में समान रूप से हक हिस्सों का निर्धारण किया जाता रहा है। प्रस्तुत वाद में पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित होने के उपरान्त भी प्रार्थीगण चाही गई इस्तदुआ हिन्दु रीति के अनुसार है। मुस्लिम विधि अनुसार कर्ता खानदान अपनी आवगी आराजी का हस्तान्तरण कर सकता है। विवादित भूमि विप्रार्थी सं. 3 को आवंटन से प्राप्त हुई है, जो कि पैतृक भूमि नहीं होकर स्वअर्जित की श्रेणी में

  
 सहायक कोलक्टर  
 SDO सिपावरी

निहीत है, ऐसी स्थिति में मुस्लिम विधि अनुसार स्वयं के नाम से भूमि अधिग्रहणकर्ता अपने स्वामित्व की सम्पूर्ण भूमि का हक त्याग करने हेतु सक्षम है तथा स्वअर्जित भूमि में स्वयं के जीवित रहने तक उत्तराधिकार की हैसियत से वारिसान दावा पेश नहीं कर सकते साथ ही यदि प्रार्थियागण विधिक वारिसान की हैसियत से अपने हक हिस्से की भूमि की इस्तदुआ चाहते तो कानून मुस्लिम विधि से अपना हक हिस्सा घोषित करवाते हुए मूल वाद में विधिवत निपटारा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु इस आवेदन के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विधिपूर्वक मनन के बाद जाहिर होता है कि अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों शर्तें 1 सुविधा का संतुलन 2 अपूरणीय क्षति 3 प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थिनीगण के पक्ष में साबित नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनीगण का आवेदन विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

  
सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी